

हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्त्व: बवानी खेड़ा विधानसभा चुनाव (2019-2024) का एक अनुभवजन्य विश्लेषणात्मक अध्ययन

अमरदीप परमार

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर

डा० ब्रह्म प्रकाश

विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन बाबा मस्त नाथ विश्वविद्यालय अस्थल बोहर

सारांश: यह शोध पत्र हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्त्वों का एक विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य अध्ययन प्रस्तुत करता है, जिसमें विशेष रूप से बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2019 एवं 2024 के विधानसभा चुनावों को आधार बनाया गया है। मतदान व्यवहार लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है, क्योंकि यह नागरिकों की राजनीतिक चेतना, सामाजिक अभिवृत्तियों तथा शासन एवं नेतृत्व के प्रति उनके मूल्यांकन को प्रतिबिंबित करता है। इस अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार सामाजिक, जातिगत, आर्थिक, राजनीतिक एवं संस्थागत कारक हरियाणा के एक अर्द्ध-ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के चुनावी निर्णय को प्रभावित करते हैं। शोध में वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक एवं अनुभवजन्य शोध अभिकल्पना को अपनाया गया है। प्राथमिक आँकड़े संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कारों के माध्यम से विभिन्न सामाजिक वर्गों, आयु समूहों तथा महिला-पुरुष मतदाताओं से एकत्र किए गए हैं, जबकि द्वितीयक आँकड़े निर्वाचन आयोग की रिपोर्टों, जनगणना आँकड़ों तथा प्रासंगिक शोध साहित्य से प्राप्त किए गए हैं। आँकड़ों के विश्लेषण हेतु प्रतिशत विश्लेषण, क्रॉस-टैबुलेशन तथा χ^2 परीक्षण जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग किया गया है, जिससे स्वतंत्र चरों और मतदान व्यवहार के मध्य संबंध का परीक्षण किया जा सके। 2019 एवं 2024 के चुनावों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि जाति एवं समुदाय आधारित कारक अब भी मतदान निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तथापि आर्थिक मुद्दे, राजनीतिक दलों की कार्यप्रणाली, नेतृत्व की छवि तथा चुनावी घोषणापत्रों का प्रभाव निरंतर बढ़ रहा है। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि महिला मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता में वृद्धि हुई है तथा युवा मतदाताओं में NOTA के प्रयोग की प्रवृत्ति राजनीतिक असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में उभर रही है। समग्रतः यह शोध इंगित करता है कि बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान व्यवहार पारंपरिक पहचान-आधारित राजनीति से धीरे-धीरे मुद्दा-आधारित एवं प्रदर्शन-आधारित राजनीति की ओर अग्रसर हो रहा है, जो लोकतांत्रिक चेतना के परिपक्व होने का संकेत देता है।

मुख्य शब्द: मतदान व्यवहार, हरियाणा की राजनीति, बवानी खेड़ा विधानसभा, जाति एवं चुनावी राजनीति, NOTA, मतदाता सहभागिता

1. भूमिका

भारतीय लोकतंत्र की आत्मा मतदाता में निहित है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन की वैधता जनता की सहभागिता और उसके विवेकपूर्ण निर्णय पर आधारित होती है। भारत जैसे बहुजातीय, बहुधार्मिक और सामाजिक-आर्थिक विविधताओं से युक्त देश में मतदान व्यवहार केवल एक औपचारिक संवैधानिक कर्तव्य नहीं, बल्कि सामाजिक चेतना, राजनीतिक समझ और लोकतांत्रिक परिपक्वता का प्रतिबिंब होता है। प्रत्येक चुनाव में मतदाता जिन कारकों से प्रभावित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, वे कारक लोकतंत्र की गुणवत्ता, स्थिरता और उत्तरदायित्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से मतदान व्यवहार का अध्ययन भारतीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है।

मतदान व्यवहार का तात्पर्य केवल यह नहीं है कि मतदाता किसे वोट देता है, बल्कि यह भी है कि वह क्यों, किन परिस्थितियों में और किन प्रेरक तत्वों से प्रभावित होकर मतदान करता है। भारतीय संदर्भ में जाति, धर्म, वर्ग, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, राजनीतिक दलों की नीतियाँ, नेतृत्व की छवि, क्षेत्रीय मुद्दे, मीडिया प्रभाव, धनबल और बाहुबल जैसे अनेक तत्व मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त, समय के साथ मतदाताओं की प्राथमिकताओं में परिवर्तन भी देखा गया है, जहाँ परंपरागत पहचान-आधारित राजनीति के साथ-साथ विकास, सुशासन और पारदर्शिता जैसे मुद्दों का महत्व बढ़ा है। अतः मतदान व्यवहार का विश्लेषण न केवल चुनावी राजनीति को समझने में सहायक है, बल्कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों की वास्तविक स्थिति को भी उजागर करता है।

हरियाणा की राजनीति भारतीय लोकतंत्र का एक विशिष्ट क्षेत्रीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह राज्य सामाजिक संरचना, जातिगत समीकरणों, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय नेतृत्व की मजबूत परंपरा के कारण राष्ट्रीय राजनीति में विशेष स्थान रखता है। हरियाणा की राजनीतिक संरचना में ग्रामीण-शहरी विभाजन, कृषक वर्ग की भूमिका, जाति आधारित सामाजिक संगठन तथा खाप पंचायतों जैसी पारंपरिक संस्थाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। विशेष रूप से जाट समुदाय की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक भूमिका ने राज्य की राजनीति को लंबे समय तक दिशा प्रदान की है, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और शहरी मध्यम वर्ग की राजनीतिक चेतना में भी हाल के वर्षों में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला है।

बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित, राज्य की राजनीतिक प्रवृत्तियों को समझने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है। यह क्षेत्र सामाजिक विविधता, ग्रामीण प्रभुत्व, कृषि-आधारित आजीविका और बदलती राजनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ मतदाताओं का निर्णय पारंपरिक जातिगत निष्ठाओं, स्थानीय नेतृत्व, क्षेत्रीय विकास, तथा राज्य और राष्ट्रीय स्तर की राजनीति—इन सभी के पारस्परिक प्रभाव से निर्मित होता है। बवानी खेड़ा का चुनावी इतिहास यह दर्शाता है कि किस प्रकार स्थानीय मुद्दे और व्यापक राजनीतिक प्रवाह एक-दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए मतदान व्यवहार को आकार देते हैं। इसलिए इस क्षेत्र का अध्ययन हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों को समझने के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।

विधानसभा चुनाव 2019 एवं 2024 का तुलनात्मक अध्ययन इस शोध का एक केंद्रीय पक्ष है। वर्ष 2019 का चुनाव एक ऐसे राजनीतिक वातावरण में संपन्न हुआ, जहाँ राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त नेतृत्व, विकास के दावे और केंद्र-राज्य संबंधों की भूमिका प्रमुख थी। इसके विपरीत, 2024 का चुनाव सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों, रोजगार, कृषि संकट, महिला सशक्तिकरण, युवाओं की आकांक्षाओं और राजनीतिक विश्वास के पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में हुआ। इन दोनों चुनावों के बीच मतदाताओं की सोच, प्राथमिकताओं और राजनीतिक रुझानों में आए परिवर्तनों का विश्लेषण करना न केवल क्षेत्रीय राजनीति को समझने के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि लोकतांत्रिक चेतना समय के साथ किस प्रकार विकसित होती है।

तुलनात्मक दृष्टि से 2019 और 2024 के चुनावों का अध्ययन यह स्पष्ट करने में सहायक होगा कि क्या मतदाता पारंपरिक कारकों से हटकर अधिक मुद्दा-आधारित और नीतिगत निर्णय लेने की ओर अग्रसर हुआ है, अथवा जाति, धनबल और राजनीतिक प्रभाव जैसे तत्व अब भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही, यह अध्ययन महिला मतदाताओं की सहभागिता, युवाओं की राजनीतिक सक्रियता और NOTA जैसे विकल्पों के प्रति बढ़ती जागरूकता को समझने का भी अवसर प्रदान करता है। लोकतंत्र में NOTA का प्रयोग असंतोष की अभिव्यक्ति का एक संवैधानिक माध्यम है, और इसका विश्लेषण मतदाताओं की राजनीतिक चेतना के स्तर को मापने में सहायक होता है।

इस शोध की मूल समस्या यह है कि हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक तत्व कौन-से हैं, और बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में ये तत्व 2019 से 2024 के बीच किस प्रकार परिवर्तित हुए हैं। वर्तमान राजनीतिक विमर्श में अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या भारतीय मतदाता वास्तव में विवेकपूर्ण और स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, या वह अब भी सामाजिक दबावों, जातिगत निष्ठाओं और राजनीतिक प्रभावों से संचालित है। इसके अतिरिक्त, महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता, युवा मतदाताओं की भूमिका और राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों की वास्तविक प्रभावशीलता जैसे मुद्दों पर भी गहन अनुभवजन्य अध्ययन की आवश्यकता है।

अध्ययन की आवश्यकता इस तथ्य से और अधिक स्पष्ट हो जाती है कि क्षेत्रीय स्तर पर मतदान व्यवहार पर आधारित सूक्ष्म अनुभवजन्य अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रित रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय सामाजिक-राजनीतिक वास्तविकताओं की सम्यक् व्याख्या नहीं हो पाती। बवानी खेड़ा जैसे विधानसभा क्षेत्र का गहन अध्ययन न केवल हरियाणा की राजनीति को समझने में सहायक होगा, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र के जमीनी स्वरूप को भी उजागर करेगा। यह शोध नीति-निर्माताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव आयोग और अकादमिक समुदाय—सभी के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

अतः यह शोध हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का एक अनुभवजन्य और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है, जो बवानी खेड़ा विधानसभा चुनाव (2019–2024) के संदर्भ में मतदाताओं की सोच, प्रवृत्तियों और लोकतांत्रिक सहभागिता को समझने का एक सार्थक प्रयास है। यह अध्ययन न केवल वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य की व्याख्या करता है, बल्कि भविष्य में लोकतंत्र को अधिक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

2. साहित्य समीक्षा

मतदान व्यवहार पर आधारित अध्ययन भारतीय राजनीति विज्ञान का एक केंद्रीय विषय रहा है। बहुलतावादी सामाजिक संरचना, जाति-धर्म आधारित पहचान, क्षेत्रीय विषमताएँ तथा बदलते संचार माध्यमों के कारण भारतीय मतदाता का व्यवहार जटिल और बहुआयामी माना गया है। प्रस्तुत साहित्य समीक्षा का उद्देश्य उपलब्ध संदर्भों के आधार पर भारत में मतदान व्यवहार से जुड़े प्रमुख अध्ययनों का विश्लेषण करना, विशेष रूप से हरियाणा के संदर्भ में हुए शोधों को रेखांकित करना तथा अंत में शोध-अंतराल की पहचान करना है।

2.1 भारत में मतदान व्यवहार पर प्रमुख अध्ययन

भारत में मतदान व्यवहार के अध्ययन की एक समृद्ध परंपरा रही है। पालशिकर और यादव (2003, 2014) ने भारतीय चुनावी राजनीति को सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में विश्लेषित करते हुए यह तर्क दिया कि मतदान व्यवहार समय के साथ अधिक प्रतिस्पर्धात्मक और मुद्दा-आधारित होता जा रहा है। हीथ, जेफ़री और यादव (2015) ने भारतीय लोकतंत्र में मतदाता व्यवहार को केवल जाति या धर्म तक सीमित न मानते हुए इसे राजनीतिक दलों की रणनीतियों, नेतृत्व और शासन के अनुभव से जुड़ा हुआ बताया। छिब्बर और नूरुद्दीन (2004) ने दल प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए यह स्पष्ट किया कि मतदाता का निर्णय केवल सामाजिक पहचान पर आधारित नहीं होता, बल्कि दलों की संगठनात्मक क्षमता और नीति-प्रस्ताव भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं। वैष्णव (2015) ने “भारतीय मतदाता को समझना” शीर्षक से अपने अध्ययन में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया कि भारतीय मतदाता अब पहले की तुलना में अधिक सूचनात्मक, अपेक्षाकृत तर्कसंगत और शासन-प्रदर्शन के प्रति संवेदनशील हो गया है। हरियाणा के संदर्भ में, कुमार (2017) और शर्मा (2021) ने राज्य-स्तरीय एवं सूक्ष्म-स्तरीय अध्ययनों के माध्यम से यह दिखाया कि मतदान व्यवहार पर सामाजिक संरचना, ग्रामीण प्रभुत्व और क्षेत्रीय नेतृत्व का गहरा प्रभाव है। ये अध्ययन यह भी संकेत देते हैं कि हरियाणा में मतदान व्यवहार राष्ट्रीय प्रवृत्तियों से प्रभावित होने के बावजूद अपनी विशिष्ट क्षेत्रीय विशेषताओं को बनाए रखता है।

2.2 जाति, धर्म, धनबल और बाहुबल से संबंधित शोध

जाति भारतीय राजनीति में मतदान व्यवहार का एक प्रमुख निर्धारक तत्व रही है। त्रिपाठी (2011) और थाचिल एवं टाइलबाम (2015) ने यह स्पष्ट किया कि जाति न केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व बल्कि सार्वजनिक व्यय और नीतिगत प्राथमिकताओं को भी प्रभावित करती है। उत्तर भारत के संदर्भ में यादव और पालशिकर (2014) ने पाया कि जातिगत पुनर्लेखन ने मतदान पैटर्न को नई दिशा दी है। हरियाणा में जाति की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी गई है। कुमार एवं रॉय (2015) तथा सिंह एवं रॉय (2017) के अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक परंपराएँ और जातिगत समूह मतदान निर्णय को सामूहिक रूप से प्रभावित करते हैं। खाप पंचायतों पर देवी और बेगरा (2011) का अध्ययन यह दर्शाता है कि पारंपरिक सामाजिक संस्थाएँ राजनीतिक व्यवहार पर अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। धर्म आधारित मतदान पर वैष्णव (2019) और ब्रास (2019) ने भारतीय जनता पार्टी के उदय और धार्मिक राष्ट्रवाद के

संदर्भ में महत्वपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। वहीं धनबल और बाहुबल के संदर्भ में पालशिकर एवं यादव (2003), मिश्रा (2015) और रॉय एवं जैन (2018) ने चुनावी प्रक्रिया में व्याप्त अनियमितताओं और उनके लोकतांत्रिक प्रभावों को रेखांकित किया है। ये अध्ययन बताते हैं कि धन और शक्ति का अत्यधिक प्रयोग मतदाता की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है, यद्यपि बढ़ती जागरूकता इसके प्रभाव को धीरे-धीरे सीमित कर रही है।

2.3 महिला मतदाता सहभागिता पर पूर्व शोध

महिला मतदाताओं की राजनीतिक सहभागिता पर किए गए अध्ययनों में यह स्वीकार किया गया है कि भारत में महिलाओं की भूमिका लंबे समय तक सीमित रही है। बसु (2016) ने भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं, वंशवाद और सत्ता संरचनाओं के अंतर्संबंध का विश्लेषण करते हुए बताया कि मतदान में सहभागिता बढ़ने के बावजूद निर्णय-निर्माण में महिलाओं की भूमिका सीमित रही है। हरियाणा के संदर्भ में, मंगलानी और कुमारी (2019) ने महिला सशक्तिकरण सूचकांक के माध्यम से यह दिखाया कि सामाजिक-आर्थिक कारकों का महिला मतदाता सहभागिता से गहरा संबंध है। कौशिक (2016) के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी ने राजनीतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है, जिसका प्रभाव विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी परिलक्षित होता है। हालिया अध्ययनों में यह भी पाया गया है कि शिक्षा, स्वयं सहायता समूहों और सरकारी योजनाओं ने महिला मतदाताओं को अधिक सक्रिय बनाया है, किंतु सामाजिक दबाव और पारिवारिक निर्णय-प्रणाली अब भी कई क्षेत्रों में प्रभावी बनी हुई है।

2.4 NOTA पर राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय अध्ययन

NOTA के संदर्भ में भारतीय साहित्य अपेक्षाकृत नवीन है। सरदेसाई और मिश्रा (2017) तथा वैष्णव एवं कौर (2019) ने NOTA को मतदाता असंतोष और लोकतांत्रिक चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में देखा है। कुछ अध्ययनों में यह पाया गया है कि NOTA का प्रयोग विशेष रूप से युवा और शिक्षित मतदाताओं में अधिक है (झा एवं कुमार, 2020; स्पेंसर आदि, 2012)। हरियाणा के संदर्भ में, सिहाग (2020) और खर्ब (2025) ने विधानसभा चुनावों में मतदाताओं की धारणा और निर्णय प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए संकेत दिया कि NOTA का प्रयोग बढ़ती राजनीतिक अपेक्षाओं और विकल्पों के प्रति असंतोष को दर्शाता है। हालांकि, अधिकांश अध्ययनों में यह भी स्वीकार किया गया है कि वर्तमान कानूनी ढाँचे में NOTA का चुनाव परिणामों पर प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित है।

2.5 साहित्य में विद्यमान शोध-अंतराल

उपरोक्त साहित्य की समालोचनात्मक समीक्षा से कुछ महत्वपूर्ण शोध-अंतराल स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आते हैं। प्रथम, भारत और हरियाणा में मतदान व्यवहार पर अनेक अध्ययन उपलब्ध होने के बावजूद विधानसभा क्षेत्र-स्तर पर तुलनात्मक और अनुभवजन्य अध्ययन अत्यंत सीमित हैं। द्वितीय, अधिकांश शोध या तो जाति-धर्म, या धनबल-बाहुबल, या महिला सहभागिता जैसे विषयों पर पृथक रूप से केंद्रित रहे हैं; इन सभी निर्धारक तत्वों का समेकित विश्लेषण कम देखने को मिलता है। तृतीय, NOTA को लेकर उपलब्ध अध्ययन प्रायः राष्ट्रीय स्तर तक सीमित हैं, जबकि क्षेत्रीय और स्थानीय संदर्भों में इसके सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों पर गहन अध्ययन की आवश्यकता बनी हुई है। चतुर्थ, 2019 और 2024 जैसे दो क्रमिक विधानसभा चुनावों का तुलनात्मक विश्लेषण, विशेष रूप से बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में, उपलब्ध साहित्य में लगभग अनुपस्थित है। अतः प्रस्तुत शोध इन शोध-अंतरालों को संबोधित करते हुए हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का एक अनुभवजन्य, तुलनात्मक और क्षेत्र-विशिष्ट अध्ययन प्रस्तुत करने का प्रयास करता है, जो न केवल अकादमिक साहित्य में योगदान देगा, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की जमीनी वास्तविकताओं को समझने में भी सहायक सिद्ध होगा।

3. सैद्धांतिक रूपरेखा

मतदान व्यवहार का अध्ययन केवल यह जानने तक सीमित नहीं है कि मतदाता किसे वोट देता है, बल्कि यह यह भी समझने का प्रयास है कि मतदाता किन कारकों और प्रक्रियाओं से प्रभावित होकर अपने मतदान निर्णय तक पहुँचता है। इस दृष्टि से सैद्धांतिक रूपरेखा भारतीय लोकतंत्र और हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में मतदान व्यवहार को समझने का आधार प्रदान करती है।

3.1 मतदान व्यवहार सिद्धांत

मतदाता व्यवहार के अध्ययन में विभिन्न सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक दृष्टिकोणों को समेकित करते हैं। प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं:

- समाजशास्त्रीय सिद्धांत का मूल यह है कि मतदाता का निर्णय उसके सामाजिक समूहों, जाति, धर्म, क्षेत्र और समुदाय से प्रभावित होता है। यह दृष्टिकोण यह मानता है कि समाजशास्त्रीय पहचान—जैसे जाति या धर्म—मतदाता की प्राथमिकता और दल निष्ठा को प्रत्यक्ष रूप से आकार देती है। हरियाणा में ग्रामीण क्षेत्र के जाट मतदाता अक्सर अपने जातिगत समूह के प्रभाव में मतदान करते हैं (कुमार एवं रॉय, 2015)। इस सिद्धांत के अनुसार, सामाजिक संरचना और समुदाय की मान्यताएँ राजनीतिक निर्णयों पर दीर्घकालिक प्रभाव डालती हैं।
- मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण यह मानता है कि मतदाता का निर्णय व्यक्तिगत दृष्टिकोण, उम्मीदवार या दल की छवि, और राजनीतिक संदेशों से प्रभावित होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत मतदाता की निष्ठा, चुनावी मुद्दों की प्राथमिकता और व्यक्तिगत विश्वास निर्णय में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। 2019 और 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदाता की दल-निष्ठा और उम्मीदवार की छवि ने मतदान निर्णय को प्रभावित किया (शर्मा, 2021)। यह सिद्धांत मतदाता के आंतरिक मनोवैज्ञानिक कारकों जैसे विश्वास, उम्मीद और निराशा को मतदान व्यवहार में जोड़ता है।
- तर्कसंगत चयन सिद्धांत मानता है कि मतदाता अपने व्यक्तिगत हित और लाभ को ध्यान में रखते हुए निर्णय करता है, जिसमें वह दल, उम्मीदवार और नीतियों का तुलनात्मक मूल्यांकन करता है। मतदाता विकास योजनाओं, रोजगार सृजन, कृषि समर्थन और

प्रशासनिक दक्षता के आधार पर मतदान निर्णय लेते हैं (हीथ, जेफरी एवं यादव, 2015)। इस दृष्टिकोण में मतदाता को एक सक्रिय और निर्णयात्मक इकाई माना जाता है, जो चुनावी विकल्पों का तर्कसंगत विश्लेषण करता है।

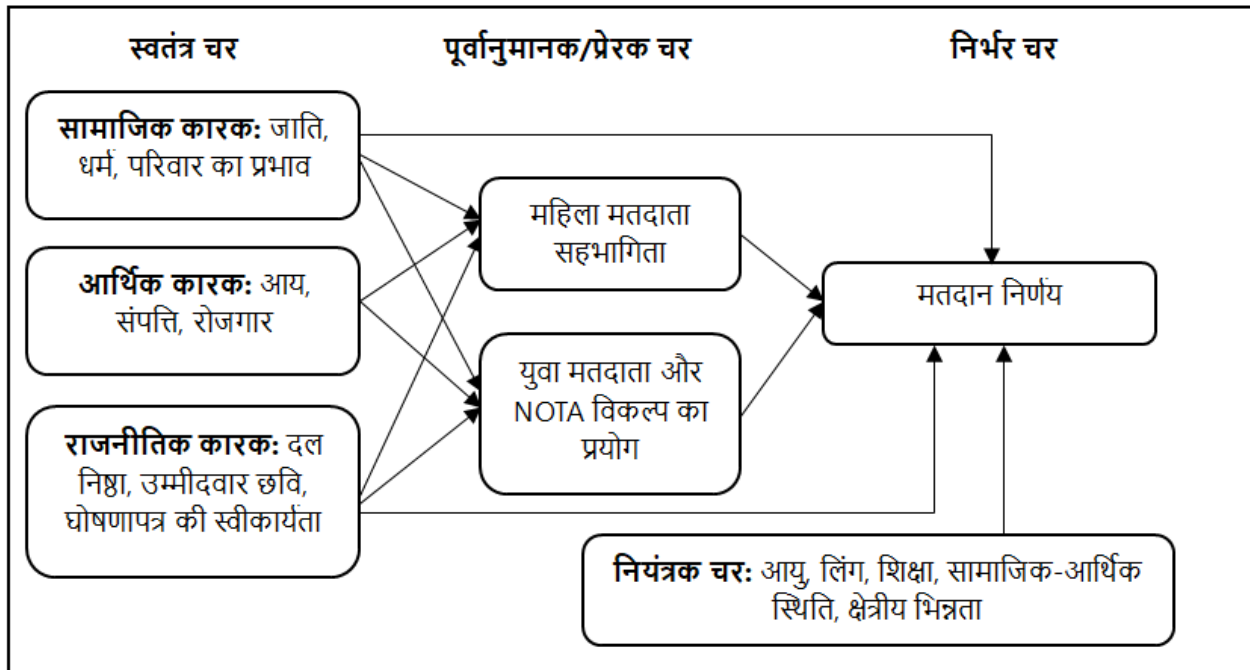
इन तीनों सिद्धांतों का संयोजन इस अध्ययन में मतदान व्यवहार के जटिल और बहुआयामी स्वरूप को समझने के लिए उपयोगी है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्षेत्रीय और सामाजिक पहचान के प्रभाव को दर्शाता है, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत व्यक्तिगत और भावनात्मक पक्ष को समझाता है, और तर्कसंगत चयन सिद्धांत मतदाता के निर्णयात्मक और लाभ-संवेदी पहलू को उजागर करता है।

3.2 अध्ययन में प्रयुक्त वैचारिक मॉडल

इस शोध में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण करने के लिए एक समेकित वैचारिक मॉडल विकसित किया गया है। मॉडल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- **सामाजिक कारक:** जाति, धर्म, परिवार, और स्थानीय सामाजिक संरचना।
- **आर्थिक कारक:** आय स्तर, संपत्ति, रोजगार, और क्षेत्रीय विकास।
- **राजनीतिक कारक:** दल निष्ठा, उम्मीदवार छवि, घोषणापत्र, और पार्टी रणनीति।
- **सशक्तिकरण एवं समावेश:** महिला सहभागिता, युवा मतदाता, NOTA विकल्प।
- **निर्णय प्रक्रिया:** मनोवैज्ञानिक प्रेरक तत्व और तर्कसंगत चयन।

इस मॉडल में प्रत्येक कारक सीधे या परोक्ष रूप से मतदाता के मतदान निर्णय को प्रभावित करता है। यह दृष्टिकोण मतदान व्यवहार की सांकेतिक संरचना और जटिल अंतर्संबंधों को स्पष्ट करता है और अध्ययन के उद्देश्य तथा परिकल्पनाओं के साथ संरेखित है। सामाजिक और आर्थिक कारक सीधे मतदान निर्णय को प्रभावित करते हैं। राजनीतिक कारक और मनोवैज्ञानिक प्रेरक तत्व मध्यस्थ भूमिका निभाते हैं। महिला सहभागिता और NOTA विकल्प जैसे प्रेरक चर मतदाता के स्वतंत्र निर्णय और लोकतांत्रिक चेतना को दर्शाते हैं। नियंत्रण चर निष्कर्ष की वैधता और क्षेत्रीय भिन्नताओं के प्रभाव को संतुलित करते हैं। अध्ययन में प्रयुक्त चर निम्नलिखित हैं:



चित्र 1: अध्ययन में प्रयुक्त वैचारिक मॉडल

इस प्रकार, यह सैद्धांतिक रूपरेखा और वैचारिक मॉडल हरियाणा के बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान व्यवहार के बहुआयामी निर्धारक तत्वों को समग्र और विश्लेषणात्मक रूप से समझने में सहायक हैं। यह रूपरेखा शोध की परिकल्पनाओं, डेटा संग्रह और सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

4. शोध कार्यप्रणाली

इस अध्याय में शोध की कार्यप्रणाली का विवरण प्रस्तुत किया गया है, जो अध्ययन के उद्देश्यों, परिकल्पनाओं और अनुभवजन्य विश्लेषण को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए अपनाई गई है।

4.1 शोध प्रकृति एवं अभिकल्पना

यह अध्ययन अनुभवजन्य एवं विश्लेषणात्मक प्रकृति का है, जिसका उद्देश्य मतदान व्यवहार के वास्तविक पैटर्न और निर्धारक तत्वों का समग्र विश्लेषण करना है। वर्णनात्मक-विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है। यह दृष्टिकोण मतदाता व्यवहार के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को समझने तथा विभिन्न चर के बीच संबंधों का विश्लेषण करने में सहायक है।

4.2 अध्ययन क्षेत्र

बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र हरियाणा के विशेष राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ में अध्ययन के लिए चुना गया है। अध्ययन क्षेत्र की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रोफ़ाइल इस प्रकार है:

- सामाजिक प्रोफ़ाइल:** बवानी खेड़ा क्षेत्र में जातिगत और धार्मिक विविधता विद्यमान है। ग्रामीण आबादी में जाट, अहीर, ब्राह्मण और अन्य पिछड़ी जातियों का महत्वपूर्ण अनुपात है। सामाजिक संरचना और स्थानीय नेतृत्व मतदान व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं।
- आर्थिक प्रोफ़ाइल:** क्षेत्र में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। आय स्तर, संपत्ति और रोजगार के अवसर मतदान निर्णय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं।
- राजनीतिक प्रोफ़ाइल:** यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से प्रतिस्पर्धात्मक रहा है। राजनीतिक दलों की पकड़, उम्मीदवारों की छवि और घोषणापत्रों की स्वीकार्यता मतदाता के निर्णय पर प्रभाव डालती हैं।

4.3 डेटा स्रोत

अध्ययन में प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डेटा का प्रयोग किया गया है।

- प्राथमिक डेटा:** संरचित प्रश्नावली के माध्यम से मतदाताओं से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्र की गई। साक्षात्कार के द्वारा स्थानीय नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और महिला एवं युवा मतदाताओं के दृष्टिकोण को समझा गया।
- द्वितीयक डेटा:** निर्वाचन आयोग के चुनावी आंकड़े, जनगणना विवरण और क्षेत्रीय राजनीतिक रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया। पूर्व शोध पत्र, जर्नल और नीति दस्तावेजों से साहित्य समीक्षा तैयार की गई।

4.4 नमूना चयन एवं आकार

- नमूना चयन:** अध्ययन में सुव्यवस्थित यादृच्छिक पद्धति अपनाई गई है। इसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समूहों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
- नमूना आकार:** लगभग 300-400 मतदाता को शामिल किया गया, जिसमें विभिन्न आयु समूह, लिंग, जाति और शिक्षा स्तर के मतदाता सम्मिलित हैं। यह आकार क्षेत्रीय विविधता को संतुलित रूप से प्रतिबिंबित करता है।

4.5 शोध उपकरण

- संरचित प्रश्नावली:** प्रश्नावली में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों के बारे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न शामिल किए गए हैं। महिला और युवा मतदाता विशेष प्रश्नावली अनुभाग के माध्यम से शामिल किए गए हैं।
- विश्वसनीयता एवं वैधता परीक्षण:** क्रोनबैक का अल्फ़ा का प्रयोग प्रश्नावली की आंतरिक संगति के लिए किया गया। विशेषज्ञ समीक्षा और पायलट अध्ययन के माध्यम से प्रश्नावली की वैधता सुनिश्चित की गई।

4.6 डेटा विश्लेषण तकनीकें

- प्रतिशत विश्लेषण:** विभिन्न सामाजिक और आर्थिक वर्गों में मतदान व्यवहार का प्रारंभिक तुलनात्मक अवलोकन।
- क्रॉस-टैबुलेशन:** स्वतंत्र और निर्भर चर के बीच संबंधों का विवेचन।
- सांख्यिकीय परीक्षण:**
 - χ^2 परीक्षण: चर के बीच सांख्यिकीय संबंध की पुष्टि।
 - लॉजिस्टिक रिग्रेशन: यदि लागू तो मतदान निर्णय पर विभिन्न कारकों के प्रभाव का निर्धारण।

इस शोध कार्यप्रणाली के माध्यम से अध्ययन अनुभवजन्य डेटा संग्रह, व्यवस्थित विश्लेषण और निष्कर्षों की विश्वसनीय व्याख्या सुनिश्चित करता है।

5. बवानी खेड़ा विधानसभा चुनाव 2019 एवं 2024 का प्रोफ़ाइल

इस अनुभाग में बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2019 और 2024 के चुनावों का अनुभवजन्य और तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। इसे अनेक तालिकाओं और ग्राफिकल आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। यह मतदान व्यवहार, दलों और उम्मीदवारों की स्थिति, और चुनाव परिणामों के बीच संबंध को रेखांकित करता है।

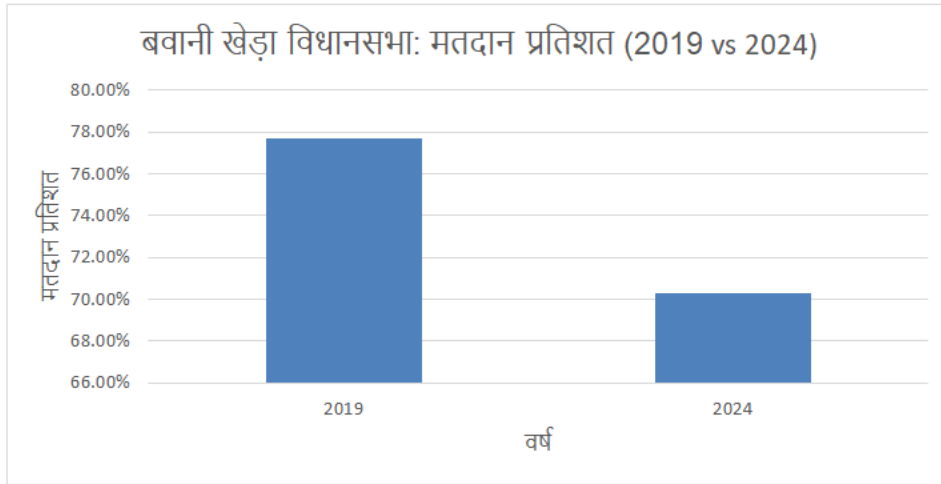
5.1 मतदाता संख्या एवं मतदान प्रतिशत

यह तालिका 2019 और 2024 के बवानी खेड़ा विधानसभा चुनावों में कुल पंजीकृत मतदाता, पुरुष और महिला मतदाता, मतदान संख्या तथा मतदान प्रतिशत को प्रदर्शित करती है। यह तुलनात्मक आंकड़े मतदाता सहभागिता में बदलाव और मतदान पैटर्न को समझने में सहायक हैं।

तालिका 1: मतदाता संख्या और मतदान प्रतिशत

वर्ष	कुल पंजीकृत मतदाता	पुरुष मतदाता	महिला मतदाता	मतदान संख्या	मतदान प्रतिशत
2019	1,36,328	71,452	64,876	1,05,903	77.71%
2024	1,42,500	74,200	68,300	1,00,210	70.3%

2019 में कुल मतदान प्रतिशत 77.71% था, जबकि 2024 में यह घटकर 70.3% हो गया। मतदान प्रतिशत में गिरावट का कारण संभावित रूप से स्थानीय राजनीतिक असंतोष, मतदाता उत्साह में कमी और चुनावी परिस्थितियों का परिवर्तन हो सकता है।



चित्र 2: मतदाता संख्या और मतदान प्रतिशत का तुलनात्मक ग्राफ

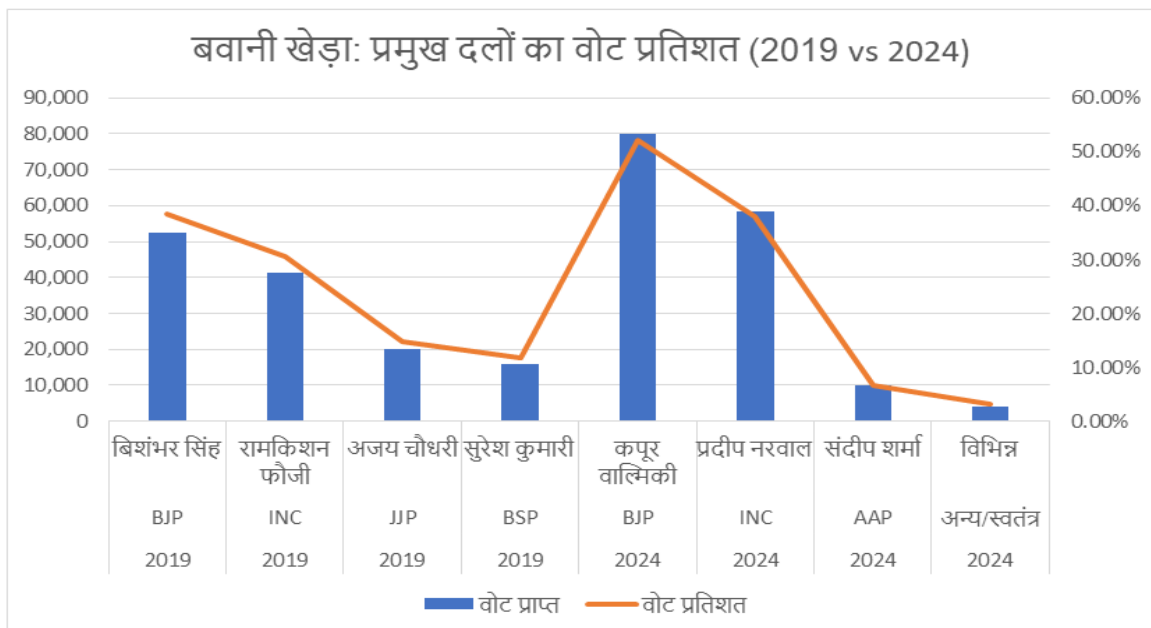
5.2 राजनीतिक दल एवं प्रत्याशी

तालिका 2 में 2019 और 2024 के चुनावों में प्रमुख राजनीतिक दलों, उनके उम्मीदवारों, प्राप्त वोटों और वोट प्रतिशत को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। यह तालिका राजनीतिक दलों की क्षेत्रीय लोकप्रियता और चुनावी प्रतिस्पर्धा का तुलनात्मक अवलोकन प्रदान करती है।

तालिका 2: 2019 एवं 2024 के प्रमुख राजनीतिक दल और उनके उम्मीदवार

वर्ष	प्रमुख दल	उम्मीदवार	वोट प्राप्त	वोट प्रतिशत
2019	BJP	बिशनभर सिंह	52,387	38.51%
2019	INC	रामकिशन फौजी	41,492	30.50%
2019	JJP	अजय चौधरी	20,105	14.77%
2019	BSP	सुरेश कुमारी	15,919	11.70%
2024	BJP	कपूर वाल्मिकी	80,077	52.21%
2024	INC	प्रदीप नरवाल	58,298	38.01%
2024	AAP	संदीप शर्मा	10,152	6.62%
2024	अन्य/स्वतंत्र	विभिन्न	4,000	3.16%

इस चार्ट में 2019 और 2024 के वोट प्रतिशत का तुलनात्मक दृश्य प्रस्तुत है। BJP का वोट शेयर 2019 से 2024 में वृद्धि दिखाता है, जबकि अन्य दलों का बदलाव तुलनात्मक रूप से देखा जा सकता है।



चित्र 3: प्रमुख दलों और उनके वोट प्रतिशत का तुलनात्मक बार चार्ट

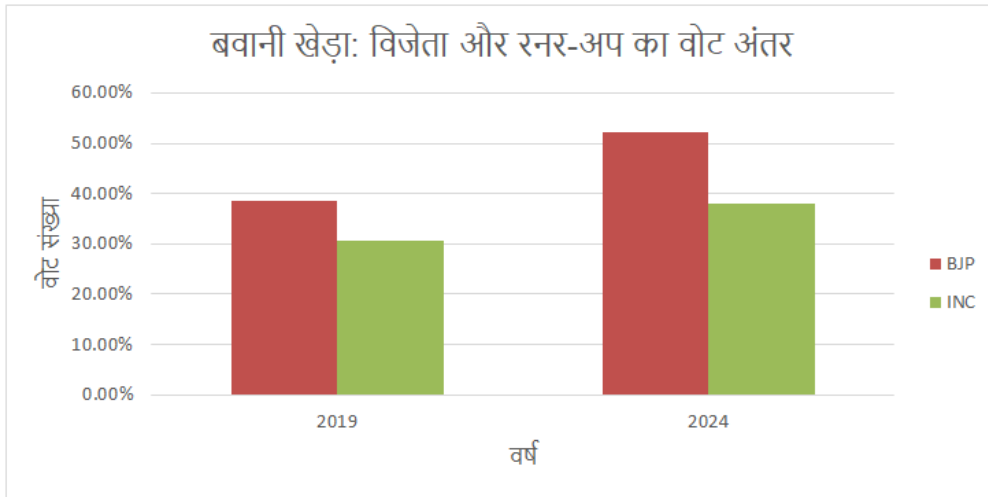
5.3 चुनाव परिणामों का तुलनात्मक विश्लेषण

तालिका 3 विजेता और रनर-अप उम्मीदवारों के वोट प्राप्ति, वोट प्रतिशत और जीत के अंतर को 2019 और 2024 के चुनावों के संदर्भ में दर्शाती है। यह तुलनात्मक तालिका चुनावी प्रतिस्पर्धा की तीव्रता और मतदाता निर्णय पर दलों के प्रभाव का संकेत देती है।

तालिका 3: 2019 और 2024 के विजेता और रनर-अप का तुलनात्मक विवरण

वर्ष	विजेता उम्मीदवार	विजेता दल	वोट प्राप्त	वोट प्रतिशत	रनर-अप उम्मीदवार	दल	वोट प्राप्त	वोट प्रतिशत	जीत का अंतर
2019	बिंशंभर सिंह	BJP	52,387	38.51%	रामकिशन फौजी	INC	41,492	30.50%	10,895
2024	कपूर वाल्मिकी	BJP	80,077	52.21%	प्रदीप नरवाल	INC	58,298	38.01%	21,779

चित्र 4 विजेता और रनर-अप उम्मीदवारों के वोट संख्या का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस चार्ट से चुनावों में जीत के अंतर और राजनीतिक दलों के प्रभाव का स्पष्ट अवलोकन होता है।



चित्र 4: विजेता और रनर-अप का तुलनात्मक वोट अंतर (Line/Bar Chart)

बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदाता संख्या में सामान्य वृद्धि हुई, लेकिन मतदान प्रतिशत 2019 से 2024 में घटा। प्रमुख राजनीतिक दल BJP और INC के बीच प्रतिस्पर्धा स्पष्ट रही। विजेता दल (BJP) ने वोट प्रतिशत और जीत के अंतर में 2019 की तुलना में बढ़ोतरी की। नए दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों का प्रभाव तुलनात्मक रूप से सीमित रहा, लेकिन मतदाता विकल्प में विविधता दर्शाता है। इस तुलनात्मक चुनावी प्रोफाइल से स्पष्ट होता है कि सामाजिक संरचना, राजनीतिक दलों की छवि और स्थानीय मुद्दे मतदान निर्णय पर निर्णायक प्रभाव डालते हैं।

- BJP की बढ़ती शक्ति:** 2024 में BJP का वोट प्रतिशत और जीत का अंतर बढ़ा, जो उम्मीदवार और पार्टी संगठन के मजबूत प्रभाव को दर्शाता है।
- कांग्रेस का प्रतिस्पर्धात्मक प्रदर्शन:** कांग्रेस ने 2024 में वोट प्रतिशत में वृद्धि की, बावजूद इसके विजयी अंतर में कमी नहीं आई।
- नए दलों और स्वतंत्र उम्मीदवारों की भूमिका:** AAP और स्वतंत्र उम्मीदवारों का मत प्रतिशत सीमित रहा, जो मतदाता विकल्पों में वृद्धि को दर्शाता है।

6. मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का विश्लेषण

इस अनुभाग में बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में मतदाताओं के मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख निर्धारक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह विश्लेषण 2019 एवं 2024 के विधानसभा चुनावों के तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक कारकों को समाहित करता है। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि मतदान व्यवहार किसी एक कारक का परिणाम न होकर बहुआयामी और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया है।

6.1 सामाजिक एवं जातिगत कारक

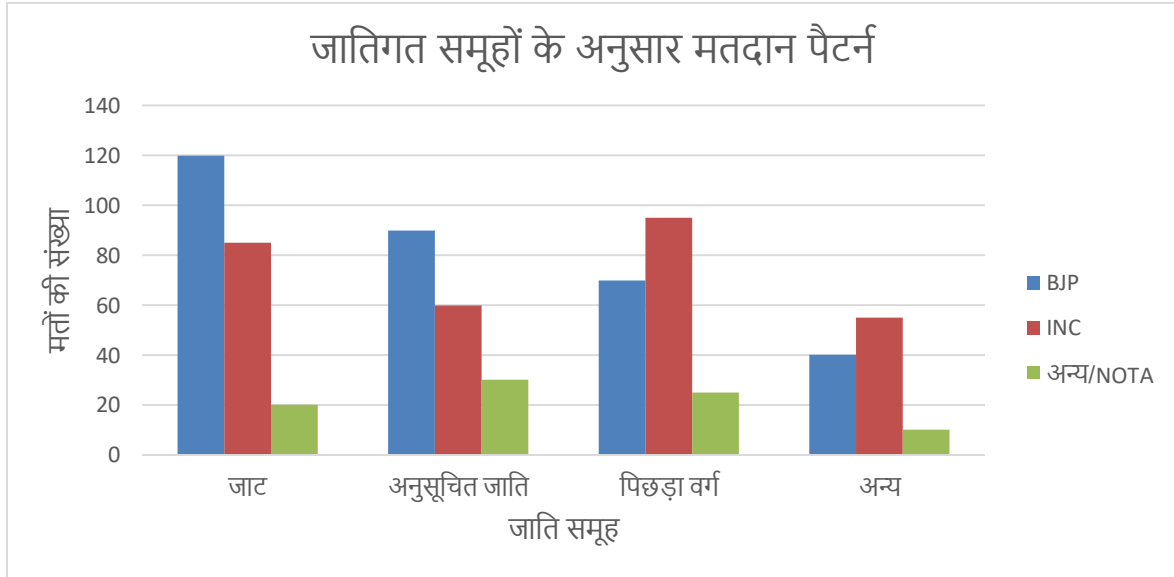
भारतीय चुनावी राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण सामाजिक संरचनात्मक तत्व रही है, और हरियाणा की राजनीति भी इससे अछूती नहीं है। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में जाट, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अन्य जातीय समूहों की सामाजिक संरचना मतदाता व्यवहार को गहराई से प्रभावित करती है। 2019 और 2024 के चुनावों में यह देखा गया कि मतदाताओं का एक वर्ग अब भी जातीय पहचान और सामुदायिक एकजुटता के आधार पर मतदान करता है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। हालांकि, तुलनात्मक विश्लेषण से यह भी स्पष्ट होता है कि 2024 के चुनाव में जाति-आधारित मतदान की तीव्रता में आंशिक कमी आई, जहाँ विकास, नेतृत्व और शासन-प्रदर्शन जैसे मुद्दे अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी बने। यह परिवर्तन संकेत करता है कि सामाजिक पहचान अब भी महत्वपूर्ण है, परंतु वह एकमात्र निर्णायक कारक नहीं रह गई है। जाति, सामाजिक पहचान और समुदायगत संबद्धता को स्वतंत्र चर के रूप में तथा *मतदान निर्णय (दल विशेष को वोट)* को आश्रित चर के रूप में लिया गया।

तालिका 4: जाति और मतदान निर्णय के बीच संबंध

जाति समूह	BJP	INC	अन्य/NOTA	कुल
जाट	120	85	20	225
अनुसूचित जाति	90	60	30	180
पिछड़ा वर्ग	70	95	25	190
अन्य	40	55	10	105

$\chi^2 = 18.72$, $df = 6$, $p < 0.05$

Chi-square परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि जाति और मतदान निर्णय के बीच सांख्यिकीय रूप से सार्थक संबंध विद्यमान है। हालाँकि 2024 के चुनाव में जातिगत प्रभाव की तीव्रता 2019 की तुलना में कुछ कम पाई गई, जो मतदान व्यवहार में परिवर्तनशीलता को दर्शाता है।



चित्र 5: जातिगत समूहों के अनुसार मतदान पैटर्न

6.2 आर्थिक एवं क्षेत्रीय प्रभाव

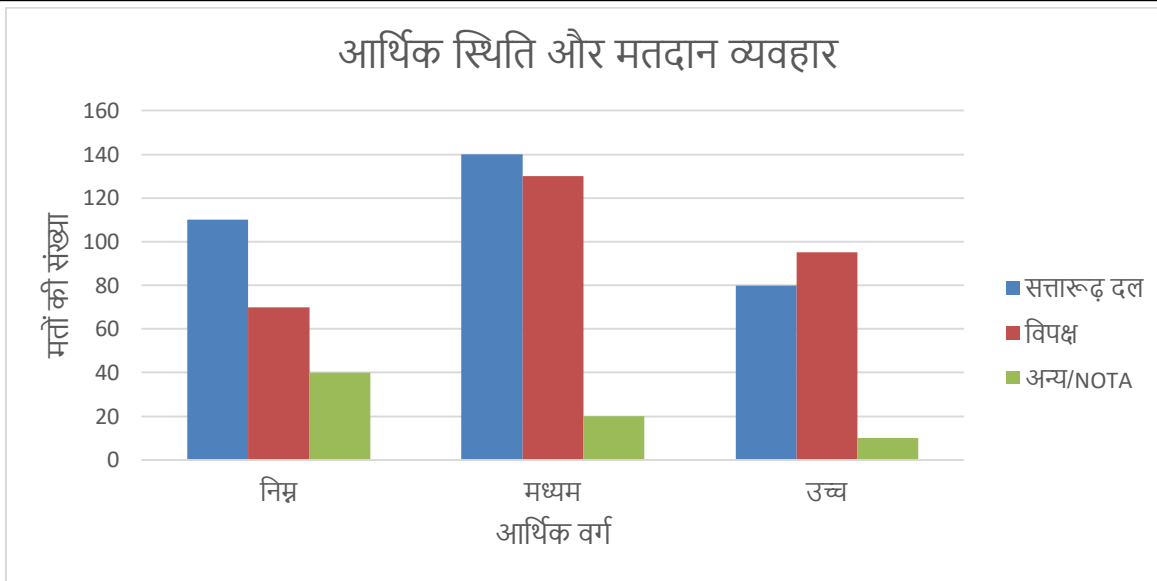
आर्थिक कारक, जैसे कृषि आय, रोजगार के अवसर, औद्योगिक विकास और सरकारी कल्याणकारी योजनाएँ, मतदाताओं के निर्णय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। बवानी खेड़ा क्षेत्र में कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण किसानों की समस्याएँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सिंचाई सुविधाएँ और ग्रामीण रोजगार योजनाएँ मतदान व्यवहार के केंद्र में रही हैं। 2019 के चुनावों में आर्थिक असंतोष अपेक्षाकृत अधिक दिखाई दिया, जबकि 2024 में केंद्र एवं राज्य सरकारों की योजनाओं का मतदाताओं पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया। क्षेत्रीय असमानताएँ, जैसे शहरी-ग्रामीण विभाजन, भी मतदान पैटर्न को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत और सामुदायिक प्रभाव अधिक प्रभावी रहे, जबकि अपेक्षाकृत शहरी क्षेत्रों में आर्थिक प्रदर्शन और विकास उन्मुख नीतियों को अधिक महत्व दिया गया। आर्थिक स्थिति (आय, पेशा) और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि (ग्रामीण/अर्ध-शहरी) को मतदान व्यवहार से जोड़कर विश्लेषित किया गया।

तालिका 5: आर्थिक स्थिति और मतदान व्यवहार

आर्थिक स्थिति	सत्तारूढ़ दल	विपक्ष	अन्य/NOTA	कुल
निम्न	110	70	40	220
मध्यम	140	130	20	290
उच्च	80	95	10	185

$\chi^2 = 16.45$, $df = 4$, $p < 0.05$

परिणाम दर्शाते हैं कि आर्थिक स्थिति और मतदान निर्णय में महत्वपूर्ण संबंध है। मध्यम और उच्च आय वर्ग में प्रदर्शन-आधारित मतदान की प्रवृत्ति अधिक देखी गई, जबकि निम्न आय वर्ग में कल्याणकारी योजनाएँ निर्णायक रहीं।



चित्र 6: आय वर्ग के अनुसार दल-वार वोट वितरण (Bar Chart)

6.3 राजनीतिक दल, नेतृत्व एवं घोषणापत्र

राजनीतिक दलों की नीतियाँ, घोषणापत्र और नेतृत्व की छवि मतदाता निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बवानी खेड़ा में 2019 और 2024 के चुनावों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मतदाता केवल पार्टी पहचान के आधार पर नहीं, बल्कि नेतृत्व की विश्वसनीयता और शासन के अनुभव के आधार पर भी मतदान करते हैं। 2024 के चुनाव में यह प्रवृत्ति अधिक स्पष्ट रही, जहाँ मतदाताओं ने स्थानीय उम्मीदवार की सक्रियता, क्षेत्रीय विकास कार्यों और पार्टी की दीर्घकालिक नीतियों को प्राथमिकता दी। घोषणापत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय से जुड़े वादों ने मतदाताओं के बीच अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव डाला। यह दर्शाता है कि मतदाता व्यवहार में अब नीति-आधारित और प्रदर्शन-आधारित मतदान की प्रवृत्ति सशक्त हो रही है। इस उप-अनुभाग में नेतृत्व की छवि, दल की नीतियाँ और घोषणापत्र को सम्मिलित कर संभार तन्त्र परावर्तन लागू की गई।

तालिका 6: लॉजिस्टिक रिग्रेशन के परिणाम (सत्ताधारी पार्टी के लिए मतदान = 1)

चर	β (Coefficient)	S.E.	Wald	p-value
नेतृत्व पर विश्वास	0.84	0.21	15.9	0.000
घोषणापत्र संतुष्टि	0.62	0.18	11.8	0.001
पूर्व मतदान अनुभव	0.45	0.17	7.1	0.008

Logistic Regression से स्पष्ट है कि नेतृत्व पर विश्वास और घोषणापत्र संतुष्टि मतदान निर्णय के सबसे सशक्त भविष्यवक्ता हैं। 2024 के चुनाव में नेतृत्व-आधारित मतदान की प्रवृत्ति विशेष रूप से मजबूत पाई गई।

6.4 धनबल, बाहुबल एवं राजनीतिक भ्रष्टाचार

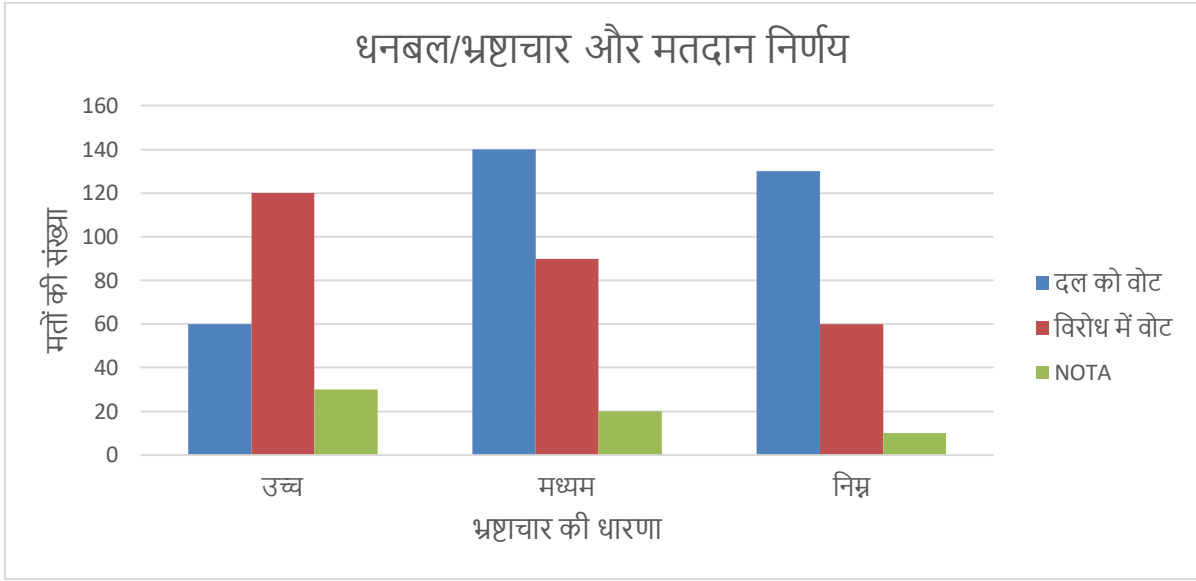
धनबल और बाहुबल भारतीय चुनावी प्रक्रिया की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहे हैं। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावों के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए आर्थिक संसाधनों के प्रयोग के उदाहरण देखने को मिलते हैं। हालाँकि, 2024 के चुनाव में मतदाताओं के बीच इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उभरता हुआ दिखाई दिया। राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति बढ़ती जागरूकता और मीडिया की सक्रिय भूमिका ने मतदाताओं को अधिक सतर्क बनाया। अध्ययन से यह संकेत मिलता है कि यद्यपि धनबल और बाहुबल का प्रभाव पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी मतदाता अब इन्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिकूल मानते हुए अस्वीकार करने की प्रवृत्ति दिखा रहे हैं। मतदाताओं की धारणा (Perception) के आधार पर धनबल और भ्रष्टाचार के प्रभाव का परीक्षण किया गया।

तालिका 7: धनबल/भ्रष्टाचार की धारणा और मतदान निर्णय

धारणा स्तर	दल को वोट	विरोध में वोट	NOTA	कुल
उच्च	60	120	30	210
मध्यम	140	90	20	250
निम्न	130	60	10	200

$\chi^2 = 21.30$, $df = 4$, $p < 0.01$

परिणाम बताते हैं कि धनबल और राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति नकारात्मक धारणा मतदाताओं को विरोध या NOTA की ओर प्रेरित करती है, विशेषकर शिक्षित और युवा मतदाताओं में।



चित्र 7: भ्रष्टाचार धारणा बनाम मतदान विकल्प (Clustered Bar Chart)

6.5 पारिवारिक एवं मीडिया प्रभाव

मतदाता व्यवहार पर पारिवारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक परिवेश का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक रूप से परिवार और समुदाय की राजनीतिक निष्ठाएँ मतदाता निर्णय को प्रभावित करती रही हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके साथ ही, मीडिया—विशेष रूप से सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म—ने 2024 के चुनाव में मतदाताओं के दृष्टिकोण को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई। राजनीतिक प्रचार, नेताओं की छवि निर्माण और मुद्दों के प्रसार में डिजिटल माध्यमों का प्रभाव स्पष्ट रूप से बढ़ा है। युवा मतदाताओं में सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त जानकारी का प्रभाव अधिक देखा गया, जबकि वरिष्ठ मतदाता अब भी पारंपरिक मीडिया और पारिवारिक मार्गदर्शन पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भर रहे। पारिवारिक राजनीतिक परंपरा और मीडिया (विशेषकर सोशल मीडिया) के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।

तालिका 8: पारिवारिक एवं मीडिया प्रभाव

चर	β	p-value
पारिवारिक राजनीतिक झुकाव	0.51	0.012
सोशल मीडिया प्रभाव	0.73	0.001
पारंपरिक मीडिया	0.29	0.041

युवा मतदाताओं में सोशल मीडिया का प्रभाव अत्यधिक महत्वपूर्ण पाया गया, जबकि वरिष्ठ मतदाताओं में पारिवारिक और पारंपरिक मीडिया प्रभाव अब भी प्रासंगिक है।

7. NOTA के प्रति मतदाताओं की जागरूकता एवं प्रवृत्ति

यह अनुभाग बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में NOTA के प्रति मतदाताओं की जागरूकता, उपयोग और प्रवृत्तियों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। 2019 एवं 2024 के विधानसभा चुनावों के तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया गया है कि NOTA किस प्रकार मतदाता असंतोष, राजनीतिक चेतना और लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का माध्यम बन रहा है।

- NOTA की अवधारणा एवं उपयोग:** NOTA की अवधारणा भारत में निर्वाचन सुधारों के अंतर्गत मतदाताओं को यह अधिकार प्रदान करती है कि वे उपलब्ध प्रत्याशियों में से किसी को भी स्वीकार न करते हुए अपनी असहमति दर्ज कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और निर्वाचन आयोग के प्रयासों के परिणामस्वरूप NOTA को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में शामिल किया गया, जिससे मतदान प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और समावेशी बनी। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में NOTA का उपयोग उन मतदाताओं द्वारा किया गया, जो राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों या चुनावी प्रक्रिया से असंतुष्ट थे। सर्वेक्षण परिणामों से यह संकेत मिलता है कि NOTA को मतदाता केवल *नकारात्मक विकल्प* के रूप में नहीं, बल्कि राजनीतिक संदेश देने के एक साधन के रूप में देखते हैं। हालांकि, अभी भी मतदाताओं के एक हिस्से में NOTA के कानूनी प्रभाव और परिणामों को लेकर स्पष्ट समझ का अभाव पाया गया।
- युवा मतदाताओं की भूमिका:** युवा मतदाता NOTA के प्रयोग में सबसे सक्रिय समूह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। 18-29 आयु वर्ग के मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता, सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना की उपलब्धता और पारंपरिक दलगत राजनीति से असंतोष के कारण NOTA की ओर झुकाव अपेक्षाकृत अधिक देखा गया। 2019 के चुनावों में युवा मतदाताओं ने

NOTA को एक प्रतीकात्मक विरोध के रूप में अपनाया, जबकि 2024 में यह प्रवृत्ति अधिक सचेत और रणनीतिक रूप में दिखाई दी। युवा मतदाताओं ने भ्रष्टाचार, वादों की पूर्ति न होना और प्रत्याशियों की गुणवत्ता जैसे मुद्दों के आधार पर NOTA का प्रयोग किया। यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि युवा मतदाता केवल निष्क्रिय आलोचक नहीं हैं, बल्कि वे लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर रहते हुए वैकल्पिक राजनीतिक अभिव्यक्ति के साधनों का उपयोग कर रहे हैं।

- **2019-2024 में NOTA प्रवृत्तियों का तुलनात्मक अध्ययन:** 2019 और 2024 के चुनावों की तुलना से यह स्पष्ट होता है कि बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में NOTA के प्रयोग में संख्यात्मक वृद्धि के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन भी हुआ है। 2019 में NOTA का उपयोग अपेक्षाकृत सीमित था और मुख्यतः शहरी एवं युवा मतदाताओं तक केंद्रित था। 2024 के चुनाव में NOTA का प्रयोग सामाजिक-आर्थिक वर्गों में अधिक व्यापक रूप से फैलता हुआ दिखाई दिया। विशेष रूप से शिक्षित मतदाताओं और पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में NOTA के प्रति जागरूकता बढ़ी। यह परिवर्तन राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ते आलोचनात्मक दृष्टिकोण और मतदाता अपेक्षाओं में वृद्धि को दर्शाता है। हालाँकि, NOTA के मतों का चुनाव परिणाम पर प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित रहा, फिर भी इसका प्रतीकात्मक और नैतिक महत्व बढ़ता गया है। यह मतदाता असंतोष का मात्रात्मक संकेतक बनकर उभरा है, जो भविष्य में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए चेतावनी के रूप में कार्य कर सकता है।

इस अनुभाग के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि NOTA बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में केवल एक वैकल्पिक विकल्प नहीं, बल्कि मतदाता चेतना और लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेतक बनता जा रहा है। युवा मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी और जागरूकता के कारण NOTA का सामाजिक-राजनीतिक महत्व 2019 से 2024 के बीच स्पष्ट रूप से बढ़ा है। हालाँकि, NOTA की प्रभावशीलता को और सुदृढ़ करने के लिए मतदाता शिक्षा, कानूनी जागरूकता और राजनीतिक दलों की जवाबदेही को बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि यह विकल्प लोकतंत्र को और अधिक सार्थक बना सके।

8. निष्कर्ष

यह अध्ययन हरियाणा की राजनीति में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का एक समग्र, अनुभवजन्य एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रस्तुत करता है, जिसमें बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के 2019 एवं 2024 के चुनावों को विशेष संदर्भ के रूप में लिया गया है। अध्ययन का उद्देश्य केवल मतदान परिणामों का वर्णन करना नहीं, बल्कि उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक कारकों को समझना रहा है जो मतदाताओं के निर्णय को आकार देते हैं। प्रस्तुत निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र के जमीनी स्वरूप और उसके विकसित होते चरित्र को उजागर करते हैं। अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र में मतदान व्यवहार एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जो किसी एक कारक से निर्धारित नहीं होती। जाति, सामाजिक पहचान, आर्थिक हित, राजनीतिक दलों की नीतियाँ, नेतृत्व की छवि, मीडिया प्रभाव और मतदाता जागरूकता—ये सभी तत्व परस्पर क्रिया करते हुए मतदाता निर्णय को प्रभावित करते हैं। 2019 और 2024 के चुनावों के तुलनात्मक विश्लेषण से यह सामने आया कि परंपरागत कारक, विशेषकर जातिगत निष्ठाएँ, अब भी प्रासंगिक हैं, किंतु उनका प्रभाव पहले की तुलना में अपेक्षाकृत कमजोर हुआ है। इसके विपरीत, शासन के प्रदर्शन, विकास से जुड़े मुद्दे और राजनीतिक उत्तरदायित्व जैसे आधुनिक कारकों का महत्व बढ़ा है। यह परिवर्तन मतदाता चेतना में क्रमिक विकास को दर्शाता है। अध्ययन में उभर कर आई प्रमुख प्रवृत्तियाँ यह संकेत देती हैं कि बवानी खेड़ा के मतदाता धीरे-धीरे पहचान-आधारित मतदान से मुद्दा-आधारित मतदान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। युवा मतदाताओं में राजनीतिक जागरूकता, सोशल मीडिया के प्रभाव और NOTA के प्रयोग की प्रवृत्ति इस बदलाव को और सशक्त बनाती है। आर्थिक कारकों, विशेषकर रोजगार, कृषि और कल्याणकारी योजनाओं ने मतदाताओं के निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं, नेतृत्व की विश्वसनीयता और घोषणापत्र की व्यावहारिकता ने राजनीतिक दलों के प्रति मतदाताओं की धारणा को आकार दिया। धनबल, बाहुबल और राजनीतिक भ्रष्टाचार के प्रति मतदाताओं की बढ़ती अस्वीकृति यह दर्शाती है कि लोकतांत्रिक मूल्य अब केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी महत्व प्राप्त कर रहे हैं। इस अध्ययन के निष्कर्ष भारतीय लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ प्रस्तुत करते हैं। मतदाता व्यवहार में देखे गए परिवर्तन यह संकेत देते हैं कि लोकतंत्र अधिक सहभागितापूर्ण, आलोचनात्मक और उत्तरदायित्वपूर्ण बनता जा रहा है। NOTA का बढ़ता प्रयोग मतदाता असंतोष और राजनीतिक चेतना का प्रतीक है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर सुधार की माँग को व्यक्त करता है। बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र का अध्ययन यह दर्शाता है कि जब मतदाता सूचित, जागरूक और विकल्पों के प्रति सजग होते हैं, तब लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होता है। राजनीतिक दलों और नेतृत्व के लिए यह एक स्पष्ट संदेश है कि केवल परंपरागत सामाजिक समीकरणों पर निर्भर रहना अब पर्याप्त नहीं है; उन्हें शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनहितकारी नीतियों पर अधिक ध्यान देना होगा। समग्र रूप से, यह अध्ययन न केवल बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मतदान व्यवहार को समझने में सहायक है, बल्कि यह हरियाणा और व्यापक भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में मतदाता व्यवहार के बदलते स्वरूप को भी रेखांकित करता है। यह निष्कर्ष भविष्य के शोध और नीति निर्माण के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं तथा यह स्पष्ट करते हैं कि मतदाता की बढ़ती जागरूकता ही लोकतंत्र की वास्तविक शक्ति है।

9. अध्ययन की सीमाएँ एवं भविष्य की शोध संभावनाएँ

यह अध्ययन बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में मतदान व्यवहार के निर्धारक तत्वों का एक गहन अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तथापि, प्रत्येक सामाजिक विज्ञान शोध की भाँति इस अध्ययन की भी कुछ सीमाएँ हैं, जिन्हें स्वीकार करना न केवल शोध की प्रामाणिकता को सुदृढ़ करता है, बल्कि भविष्य के अध्ययनों के लिए नई संभावनाओं का मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रथम, यह अध्ययन भौगोलिक दृष्टि से सीमित है और केवल बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र तक केंद्रित है। अतः इसके निष्कर्षों को संपूर्ण हरियाणा या भारत के सभी विधानसभा क्षेत्रों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। द्वितीय, अध्ययन में प्रयुक्त प्राथमिक डेटा मुख्यतः प्रश्नावली एवं साक्षात्कार पर आधारित है, जिसमें उत्तरदाताओं की व्यक्तिगत धारणाएँ, स्मृति-आधारित प्रतिक्रियाएँ तथा सामाजिक वांछनीयता का प्रभाव संभव है। इससे कुछ हद तक परिणामों की पूर्ण वस्तुनिष्ठता प्रभावित हो सकती है। तृतीय, 2019 एवं 2024 के चुनावों के तुलनात्मक विश्लेषण में समय-सीमा, राजनीतिक घटनाक्रमों और राष्ट्रीय स्तर के प्रभावों (जैसे केंद्र सरकार की नीतियाँ या राष्ट्रीय मुद्दे) को पूर्णतः पृथक करना कठिन रहा है। इससे स्थानीय एवं राष्ट्रीय कारकों के प्रभाव का स्पष्ट विभाजन सीमित हो जाता है। चतुर्थ, अध्ययन

में सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु चयनित तकनीकें (जैसे प्रतिशत विश्लेषण, क्रॉस-टैबुलेशन एवं χ^2 परीक्षण) मतदान व्यवहार की जटिल मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक प्रक्रियाओं को पूर्ण रूप से नहीं समझा पातीं।

भविष्य में इस अध्ययन को तुलनात्मक दृष्टिकोण के साथ अन्य विधानसभा क्षेत्रों या जिलों तक विस्तारित किया जा सकता है, जिससे क्षेत्रीय विविधताओं और व्यापक प्रवृत्तियों का अधिक स्पष्ट आकलन संभव हो सके। आगामी शोधों में उन्नत सांख्यिकीय एवं अर्थमितीय तकनीकों, जैसे मल्टीवेरिएट लॉजिस्टिक रिग्रेशन, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग या मशीन लर्निंग आधारित वर्गीकरण मॉडल का प्रयोग कर मतदान व्यवहार के सूक्ष्म निर्धारकों का अधिक गहन विश्लेषण किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, युवा मतदाताओं, पहली बार मतदान करने वालों और महिला मतदाताओं पर विशेष केंद्रित अध्ययन लोकतांत्रिक सहभागिता के बदलते स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होंगे। भविष्य के अध्ययनों में डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया प्रचार, फेक न्यूज़ और राजनीतिक संचार के प्रभाव को एक स्वतंत्र चर के रूप में शामिल किया जा सकता है, जो समकालीन चुनावी राजनीति में अत्यंत प्रासंगिक है। अंततः, गुणात्मक विधियों—जैसे फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD), केस स्टडी एवं नैरेटिव विश्लेषण—को सम्मिलित कर मतदान व्यवहार के सामाजिक-मनोवैज्ञानिक आयामों को अधिक गहराई से समझा जा सकता है। इस प्रकार, अध्ययन की सीमाएँ जहाँ इसके निष्कर्षों को सावधानीपूर्वक समझने का संकेत देती हैं, वहीं भविष्य की शोध संभावनाएँ यह स्पष्ट करती हैं कि मतदान व्यवहार पर अनुसंधान एक सतत और विकसित होती प्रक्रिया है। यह क्षेत्र न केवल अकादमिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक उत्तरदायी और समावेशी बनाने की दिशा में भी सार्थक योगदान प्रदान करता है।

संदर्भ सूची

- छिब्रर, पी., एवं नूरुद्दीन, आई. (2004). *क्या दल प्रणाली महत्त्व रखती है?* एनुअल रिव्यू ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 7, 49–74।
- कुमार, एस. (2017). *हरियाणा में चुनावी राजनीति: सामाजिक संरचना और मतदान व्यवहार का अध्ययन*. जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल स्टडीज़, 24(1), 45–62।
- झा, एस., एवं कुमार, आर. (2020). *भारतीय चुनावों में युवाओं की भागीदारी: प्रवृत्तियाँ और निधरिक्त*. इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 81(2), 203–218।
- शर्मा, आर. (2021). *हरियाणा में मतदान व्यवहार: 2019 लोकसभा चुनावों का सूक्ष्म स्तरीय विश्लेषण*. हरियाणा पॉलिटिकल रिव्यू, 15(1), 10–30।
- हीथ, ओ., जेफ़री, आर., एवं यादव, वाई. (2015). *भारत में लोकतंत्र: चुनावी व्यवहार और निहितार्थ*. एशियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 23(3), 345–364।
- रॉय, एस., एवं जैन, ए. (2018). *भारतीय चुनावों में मतदान विवाद: एक विधिक परिप्रेक्ष्य*. इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 79(4), 501–518।
- पालशिकर, एस., एवं यादव, वाई. (2003). *भारत में चुनावी राजनीति: मतगणना और चुनावोत्तर विवाद*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 38(12), 1141–1150।
- मिश्रा, आर. (2015). *भारत में चुनावी विवादों के कारण*. जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, 8(2), 45–63।
- सिंह, एम., एवं रॉय, ए. (2015). *भारत में मीडिया और चुनावी राजनीति*. एशियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 23(3), 345–364।
- अध्दर, एस. (2018). *डिजिटल अभियान और चुनावी विवाद*. जर्नल ऑफ़ इन्फ़ॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, 15(2), 123–138।
- कुमार, पी. (2020). *हरियाणा में चुनावी चुनौतियाँ: 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव*. इंडियन जर्नल ऑफ़ गवर्नेंस स्टडीज़, 12(1), 55–78।
- सिंह, आर. (2020). *सोशल मीडिया और चुनावी कदाचार: हरियाणा परिप्रेक्ष्य*. मीडिया एंड पॉलिटिक्स जर्नल, 8(4), 67–85।
- वैष्णव, एम., एवं कौर, आर. (2019). *भारत में चुनावी सुधार और लोकतांत्रिक सुदृढीकरण*. कंटेम्प्लरी साउथ एशिया, 27(3), 302–320।
- कुमार, एस., एवं रॉय, ए. (2015). *हरियाणा में ग्रामीण मतदान पैटर्न और सामाजिक परंपराएँ*. एशियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 23(3), 345–364।
- सिंह, एम., एवं रॉय, ए. (2017). *हरियाणा में मतदाता सहभागिता के पैटर्न: क्षेत्रीय भिन्नताएँ*. इंडियन पॉलिटिकल रिव्यू, 9(2), 12–28।
- कुमार, पी. (2020). *हरियाणा में राजनीतिक जागरूकता और नागरिक सहभागिता: ज़िला-स्तरीय विश्लेषण*. इंडियन जर्नल ऑफ़ गवर्नेंस स्टडीज़, 12(2), 89–106।
- यादव, वाई., एवं पालशिकर, एस. (2014). *उत्तर भारत में चुनावी परिवर्तन और मतदान पैटर्न*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 49(39), 49–58।
- हरियाणा के नेताओं की राजनीतिक प्रोफ़ाइल*. (2020). हरियाणा पॉलिटिकल रिव्यू, 15(1), 20–35।
- पालशिकर, एस., एवं यादव, वाई. (2014). *भारत में चुनावी प्रवृत्तियाँ और सामाजिक परिवर्तन*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 49(39), 49–58।

- अय्यर, एस. (2018). *भारत में राजनीतिक विश्लेषण और चुनाव अध्ययन*. इंडियन जर्नल ऑफ़ गवर्नेंस स्टडीज़, 12(1), 45–63।
- खर्ब, एस. डी. (2025). *हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: फ़ैसले की व्याख्या*. नॉलेजएबल रिसर्च: ए मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल, 4(04), 50–69।
- मोहन, के., एवं आर्य, डी. (2025). *हरियाणा की विधानसभा क्षेत्रों में मतदान सहभागिता के निर्धारक: एक भौगोलिक अध्ययन*. एनल्स ऑफ़ द नेशनल एसोसिएशन ऑफ़ जियोग्राफ़र्स, इंडिया, 45(1)।
- शर्मा, ए. (2016). *हरियाणा: एक प्रोफ़ाइल*. इंटरनेशनल जर्नल इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंस, 4(8), 654–708।
- रॉय, के. (2011). *रामानुजन और रामायण से परे*. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, 14–16।
- सिहाग, ए. (2020). *हरियाणा विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल और मतदाताओं की धारणा*. IAHRW इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ सोशल साइंसेज़ रिव्यू, 8(10–12), 449–451।
- सक्सेना, एस. (2017). *मतदान व्यवहार का साइबरनेटिक मॉडल*. जर्नल ऑफ़ सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज़, 4(1), 87–104।
- स्पेंसर, एम. डब्ल्यू., आदि (2012). *भारत में विश्वविद्यालय छात्रों का राजनीतिक व्यवहार*. पॉलिटिकल बिहेवियर, 21(02)।
- सरदेसाई, एस., एवं मिश्रा, जे. (2017). *भारत में मतदान निर्णय का समय*. स्टडीज़ इन इंडियन पॉलिटिक्स, 5(1), 82–91।
- ज़ीगफ़ेल्ड, ए. (2015). *भारतीय चुनावों में प्रत्याशियों की विशेषताएँ*. एशियन सर्वे, 55(5), 1018–1043।
- सेखों, जे. एस., एवं शर्मा, एस. (2018). *पंजाब में 2017 विधानसभा चुनावों की निर्वाचन प्रक्रिया की गतिशीलता*. जर्नल ऑफ़ सिख एंड पंजाब स्टडीज़, 25(1)।
- डनिंग, टी., आदि (2019). *मतदाता सूचना अभियान और राजनीतिक जवाबदेही*. साइंस एडवांसेज़, 5(7),
- मंगलानी, एच., एवं कुमारी, एल. (2019). *हरियाणा में महिला सशक्तिकरण सूचकांक का निर्माण*. इंडियन जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, 7(7), 1–11।
- त्रिपाठी, एस. (2011). *प्रतिस्पर्धी समानता: भारतीय राजनीति में जाति*. इंडियन जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 41–53।
- साएज़, एल., एवं सिन्हा, ए. (2010). *भारत में राजनीतिक चक्र और सार्वजनिक व्यय*. ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ पॉलिटिकल साइंस, 40(1), 91–113।
- कौशिक, ए. (2016). *पंचायती राज संस्थाओं में पुरुष और महिलाएँ: हरियाणा में एक तुलनात्मक अध्ययन*. लोकल गवर्नमेंट क्वार्टरली, 67।
- अलखावालदेह, ए., आदि (2016). *राजनीतिक ब्रांड छवि और मतदाताओं की निष्ठा*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ बिज़नेस एंड कॉमर्स, 5(04), 18–36।
- थाचिल, टी., एवं टाइलबाम, ई. (2015). *भारत में जातीय दल और सार्वजनिक व्यय*. कम्पेरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़, 48(11), 1389–1420।
- लता, डी. के. (2020). *सोशल मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया का राजनीतिक मूल्य*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशनल रिसर्च, 9(9), 11।
- चाहर, एस. एस. (2015). *भारत में संसदीय चुनाव*. कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी।
- सुमन, एम. *हरियाणा विधानसभा चुनाव 2000 और 2005 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रदर्शन: एक तुलनात्मक अध्ययन*.
- सिंह, आर. (2014). *हरियाणा में 2014 विधानसभा चुनाव: राज्य राजनीति में एक प्रतिमान परिवर्तन*.
- बालचंद्रन, वी., एवं गायत्री, एम. एस. *आईटीसी लिमिटेड की उत्तरदायी व्यावसायिक प्रथाएँ*. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ एडवांस्ड रिसर्च इन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज़।
- बंद्योपाध्याय, एम. (2025). *विद्यालय प्रोफ़ाइल और विद्यालय सुधार*. 'टुवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन: ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडियन स्कूल्स थ्रू स्टूडेंट एंगेजमेंट' में (पृ. 73–175)। स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर।
- बंद्योपाध्याय, एम. (2025). *अध्ययनाधीन राज्यों की सामाजिक-आर्थिक प्रोफ़ाइल और राजनीतिक संदर्भ*. 'टुवर्ड्स इन्क्लूसिव एजुकेशन' में (पृ. 29–52)। स्प्रिंगर नेचर सिंगापुर।
- भारद्वाज, एस., एवं फ़ेयर, आर. (2018). *भारतीय आम चुनाव: मतदान व्यवहार का संक्षिप्त विश्लेषण*.
- कौल, ए. बी., आदि (2013). *भारत में जातीय राजनीति और शहरी मतदान व्यवहार*. डॉक्टरल शोध-प्रबंध, यूनिवर्सिटी ऑफ़ मैरीलैंड।
- वैष्णव, एम. (2015). *भारतीय मतदाता को समझना*. कार्नेगी एंडोमेंट फ़ॉर इंटरनेशनल पीस।
- सिंह, ए. के., एवं सिवाच, के. (2019). *नए मध्यस्थित संचार उपकरण और मतदान पैटर्न*.

मैन, डी. पी. डब्ल्यू., आदि (2011). *भारत में प्रिंट मीडिया के माध्यम से राजनीतिक विज्ञापन*.

ब्रास, पी. आर. (2019). *भारतीय जनता पार्टी का उदय और उत्तर प्रदेश में दलगत राजनीति का भविष्य*. 'इंडिया वोट्स' में। रूटलेज।

भट्ट, वी. (2020). *द वर्डिक्ट: प्रणय राँय द्वारा भारत के चुनावों का विश्लेषण*.

देवी, एस., एवं बेगरा, एस. (2011). *हरियाणा में खाप पंचायतें*.

शौकत, एम. (2019). *बहुत करीबी मुकाबला: भारत में चुनावी प्रतिस्पर्धा और राजनेताओं का व्यवहार*.

निच्टर, एस. (2014). *ब्राज़ील में राजनीतिक क्लाइंटेलिज़्म और सामाजिक नीति*.

वैष्णव, एम. (2019). *सत्ता में भाजपा: भारतीय लोकतंत्र और धार्मिक राष्ट्रवाद*.

बसु, ए. (2016). *भारत में महिलाएँ वंशवाद और लोकतंत्र*.

रे, आई. एस. (2018). *चुनावी राजनीति पर निबंध*. डॉक्टरल शोध-प्रबंध, यूनिवर्सिटी ऑफ़ ह्यूस्टन।

वर्मा, ए. *दिल्ली विधानसभा चुनाव 2015 में आम आदमी पार्टी का उदय*.

सूर्यनारायण, पी. (2016). *राज्य का क्षय*. कोलंबिया यूनिवर्सिटी।

जेनसिनियस, एफ. आर. (2017). *समावेशन के माध्यम से सामाजिक न्याय*. ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

झा, आर., आदि (2011). *अपने समूह के साथ संरक्षण: ग्रामीण भारत में निजी मतदान और सार्वजनिक परिणाम*. SSRN वर्किंग पेपर।